

मुख्य न्यायाधीश एम. एम. कुमार और राजेश बिंडल, जेजेए के सामने।

सुप्रीम कोर्ट स्वयं-प्रार्थी

बनाम

आर.एन. प्रशार और अन्य-उत्तराधिकारी

सीडब्ल्यूपी संख्या 2098, 2009

28 अक्टूबर, 2010

भारतीय संघ का संविधान, 1950-कल्पना 226-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-धारा 48-पुरस्कृत व्यक्ति की भूमि को पुरस्कृत करना बाद में छोड़ना-राज्य ने उसे मुआवजे को लौटाकर विकसित क्षेत्र में दो कनाल की जगह आकर्षित की है, सीधे उसकी अधिग्रहित भूमि की आपत्ति-एक बार भूमि का कब्जा लेने के बाद, धारा 48 के तहत भूमि को मुक्त करने का राज्य को कोई शक्ति नहीं है-शक्ति का दुरुपयोग और 1894 अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन-भूमि को मुक्त करने और राज्य द्वारा हुई प्लॉट की आवंटन के आदेश को खारिज किया जाता है।

(2) 1994 सप्ल. (2) एस.सी.सी. 52

यह माना जाता है कि मुख्यमंत्री-कम-चेयरमैन, हुडा की अध्यक्षता में हुई बैठक की प्रक्रिया की परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि जब भी भूमि को रिहा करने का उद्देश्य से होने वाली बैठक हुई थी, तो उत्तराधिकारी आर.एन. प्रशार को साफ दिखाई दी, शुरुवात में उन्होंने उस न्याय का उल्लंघन करने के लिए प्रयास किया जो वास्तव में पूरी तरह से मुख्यमंत्री-कम-चेयरमैन, हुडा की आगामी न्याय में बिल्कुल विपरीत था, जिसमें कहा गया था कि जब एक्क्वायर्ड लैंड का कब्जा किया जाता है, तो ऐसे कोई शक्ति राज्य के पास नहीं है कि इसे अधिग्रहण से मुक्त करे, अधिनियम की धारा 48 के तहत। इसके बावजूद, भूमि को मुक्त करने का आदेश दिया गया, हालांकि नोट में स्पष्ट रूप से इस बात को बताया गया था कि ऐसी शक्ति धारा 48 के तहत मौजूद नहीं है। इसके बावजूद, उसे इसकी जगह पर एक प्लॉट आवंटित किया गया जो उत्तराधिकारी आर.एन. प्रशार की पहले ही रिहा की जाने वाली भूमि के पास था। यह विवादित नहीं है कि भूमि को 1997 में पहले ही अधिग्रहित किया गया था और 2006 तक, जब इसका एक हिस्सा उत्तराधिकारी आर.एन. प्रशार को रिहा करने के लिए निर्देशित किया गया था, हुडा ने भूमि का उपयोग एक कनाल और दो कनाल के प्लॉट्स को बनाने के लिए किया था और उन्हें बिक्री के लिए भी प्रस्तुत किया गया था। इस बारे में यह क्यों नहीं कहा गया कि उस प्रासंगिक प्लॉट को कभी बिक्री के लिए नहीं डाला गया था, जो उत्तराधिकारी आर.एन. प्रशार की पहले ही अधिग्रहित भूमि के पास था, यह स्पष्ट है कि हालांकि उसकी भूमि अधिग्रहित हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने हुडा के साथ यह संबंधित बाजार में जमा नहीं करने की क्षमता बनाए रखी थी ताकि जिस भी समय उसके लिए आवश्यक हो, वह उस प्लॉट को अपनी प्राप्त भूमि के बदले में आवंटित कर सके।

(पैरा 38)

2. उपरोक्त कर्तव्य का पालन करते समय यह हममें से एक (राजेश बिंदल, जे.) के ध्यान में आया कि कैसे मामलों के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, जो अन्यथा होता फ़ाइल में छिपा रहा. यह एक ऐसा मामला है जहां राज्य का एक वरिष्ठ अधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के प्रावधानों को पूरी तरह से अनदेखा करके अपनी 846 वर्ग मीटर भूमि को मुक्त कराने में सक्षम हो गया था।

3 और इसे यह निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि एक बार भूमि का कब्जा राज्य द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हो गया है, तो अधिनियम की धारा 48 के तहत भूमि को मुक्त करने का अधिकार प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर स्वीकृत स्थिति यह है कि भूमि का कब्जा किया गया था। इस प्रकार, राज्य द्वारा अधिग्रहित भूमि को कब्जे के छह वर्ष बाद मुक्त करने की प्रक्रिया ने केवल शक्ति का दुरुपयोग ही किया है।

(पैरा 39)

और इसे और यह निष्कर्षित किया गया है कि एच.यू.डी.ए के द्वारा उत्तराधिकारी आर.एन. प्रशार के पक्ष में 846 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किया जाना एक आदलती अदला-बदली के रूप में चाहिए गया है। एक बार यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य द्वारा अधिग्रहित भूमि के पक्ष में रिहा करना अवैध और अर्बिट्रेरी था, जिसे राज्य स्वयं समर्थन नहीं कर सकता था, तो इसमें कोई आदलती अदला-बदली की समस्या नहीं है और उसके पश्चात्कालिक प्लॉट की आवंटन भी असफल हो जाता है। एक और कारक जिसे नोट करना चाहिए, यह है कि एच.यू.डी.ए एक्ट, 1977 की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार, इसने केवल राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी जैसा कि एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया था, जबकि तर्क के समय, यह नामांकनकर्ता आर.पी. गुप्ता के तथ्यपत्र में, हुडा (हेडक्वार्टर) पंचकुला के प्रशासक द्वारा लिखित तिथि 17 जुलाई, 2009 को लिया जाने वाला स्थान यह है कि इसने केवल राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निर्देशों का पालन किया था, जबकि तर्क के समय, लिया जाने वाला तर्क अलग था।

(पैरा 41)

और इसे और यह भी निष्कर्षित किया गया है कि एक बार यह पाया गया है कि उत्तराधिकारी आर.एन. प्रशार के पक्ष में भूमि को रिहा करना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसे राज्य भी बचा नहीं सका, भूमि राज्य में हो जाने पर। राज्य जनता का है अधिकारी है। यदि अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करके किसी पसंदीदा को लाभ मिलता है, तो अगर कोई व्यक्ति अदालत में इसका आपत्तिजनक प्रदर्शन करता है, तो अदालत हमेशा कदम उठा सकती है क्योंकि यह राज्य द्वारा बांटा जा रहा था जो एक उपहार नहीं था।

(पैरा 42)

और इसे और यह भी निष्कर्षित किया गया है कि देरी के संबंध में तर्क भी वाजिज्यिक है। वास्तव में, यह उत्तराधिकारी आर.एन. प्रशार द्वारा यह एक योजनाबद्ध डिज़ाइन था कि वह तुरंत भूमि को रिहा होने के बाद आवेदन नहीं करेगा और यह सितंबर, 2008 में इस मामले की आवश्यकता थी, जो कि भूमि को रिहा होने के बाद तुरंत किया जा सकता था। इसका उद्देश्य यह हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति ने अदालत में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले रिहा करने के पूरे प्रक्रिया में विवाद की आपत्ति को देखते हुए, देरी का तर्क करने का उद्देश्य रखा गया था। यदि कोई न्यायालय की जुरिस्टिक्शन का निवोक करता, तो यह अवश्य रूप से इस अवैध कृत्य को दृष्टि में रखने की क्षमता नहीं रख सकता है जो राज्य ने एक समय पर उपभोक्ता को पसंद किया जो उस समय में राज्य का एक वरिष्ठ कर्मचारी रहा है।

(पैरा 43)

अरुण नेहरा, अधिवक्ता अमीकस क्यूरिए।

सरजीत सिंह, उत्तराधिकारी आर.एन. प्रशार के साथ जगदेव सिंह, अधिवक्ता।

कमल सहगल, हरियाणा के अतिरिक्त अधिवक्ता महाधिवक्ता।

अरुण वालिया, हुडा के लिए वरिष्ठ स्थायी सरकारी वकील।

राजेश बिंदल, न्यायाधीश।

(1) एक न्यायाधीश का कर्तव्य स्मृति चंद्रिका में निम्नलिखित शब्दों में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है:

जैसा कि एक अनुभवी सर्जन शल्यक्रियाओं के माध्यम से एक व्यक्ति के शरीर से एक बाण निकालता है, वैसे ही मुख्य न्यायाधीश को एक कानूनी मुद्दे से अनैतिकता का बाण निकालना चाहिए सर्जिकल उपकरणों के साधनों के द्वारा।"

(नारद विदे स्मृति चंद्रिका पृ. 30)।

"जैसा कि एक कुशल सर्जन, जो एक बाण निकालने की कला में निपुण है, शल्यक्रियाओं और अन्य विविध कुशल अभ्यासों का उपयोग करके उसे निकालता है, हालांकि यह कठिन हो सकता है, जिसे अदृश्य होने के कारण प्राप्त करना मुश्किल है, वैसे ही एक न्यायाधीश को न्यायिक जांच के कुशल उपायों का उपयोग करके उस अनैतिकता के बाण को निकालना चाहिए जो किसी कानूनी मुद्दे में प्रवेश कर गया है।"

(नारद स्मृति SBE शृंगार पृ. 39 फुटनोट)।

(स्रोत: न्यायमूर्ति डॉ. एम. राम जोइस द्वारा एक संग्रह, जो कि भारतीय न्याय दर्शन और राजा धर्म में एलएलबीएम कोर्स की प्रस्तावना के समय गुलबर्गा विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ, प्रकाशित किया गया था)।

(2) इस कर्तव्य को निष्पादित करते समय, हमें यह सुचित हुआ कि कैसे वे व्यक्ति जो किसी राजा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते थे, जो अन्यथा फाइल में छिपा रह जाता। यह एक मामला है जहां राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में अधिनियम) के प्रावधानों को पूरी तरह से अनदेखा करके अपने 846 वर्ग मीटर की ज़मीन को रिहा करवा ली थी।

(3) पक्षों की संबंधित दलीलों पर विस्तार से विचार करने से पहले, मामले के तथ्यों पर ध्यान देना उचित होगा, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में राज्य के साथ-साथ हुडा की मनमानी कार्रवाई को जनहित याचिका के रूप में माना गया। . मुआवजा बढ़ाने की मांग करने वाले भूमि मालिकों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते समय यह मुद्दा इस अदालत के ध्यान में आया। चूँकि कुछ भूमि मालिकों ने अपनी अपीलें वापस लेनी शुरू कर दी थीं, इस अदालत को इसके पीछे के कारणों पर संदेह हुआ और उन्होंने राज्य के विद्वान वकील से इसके कारणों का पता लगाने को कहा। रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, यह पता चला कि प्रतिवादी- आरएन पराशर के मामले में, हालांकि उनके स्वामित्व वाली भूमि दिनांक 11.9.1997 की अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई थी। कलेक्टर द्वारा 5.9.2000 को अवार्ड घोषित कर दिया गया तथा कब्जा भी ले लिया गया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (संक्षेप में, 'कलेक्टर') द्वारा दी गई राशि को संदर्भ न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसके खिलाफ 2003 का आरएफए नंबर 818 इस अदालत में दायर किया गया था। हालाँकि, इसके लंबित रहने के दौरान, 2006 में उनके स्वामित्व वाली भूमि को राज्य सरकार द्वारा जारी करने का निर्देश दिया गया था और इसके बदले में, सेक्टर 4, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला में 846 वर्ग मीटर का एक भूखंड 2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2098 था। [3] केवल इस शर्त पर आवंटित किया गया कि वह प्राप्त मुआवजे की राशि ब्याज सहित लौटाएगा और विकास शुल्क के रूप में एक छोटी राशि का भुगतान करेगा। यह भी रिकॉर्ड में आया कि प्रतिवादी- आरएन पराशर के स्वामित्व वाली भूमि 2883 वर्ग मीटर त्रिकोणीय आकार में थी, जिसमें से 535 वर्ग मीटर भूमि पुरस्कार की घोषणा तक जारी की गई थी और शेष राशि पुरस्कार के छह साल बाद जारी की गई थी। . जारी की गई भूमि भी वही नहीं थी, जो प्रतिवादी- आरएन पराशर के स्वामित्व में थी, बल्कि क्षेत्र में पहले से ही विकसित क्षेत्र में काटे गए नियमित भूखंडों के रूप में थी।

4. इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 48 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के मददेनजर सरकार की उपरोक्त कार्रवाई को प्रथम दृष्टया अनुमेय नहीं मानते हुए , भूमि की रिहाई के संबंध में मामले को एक के रूप में मानने का निर्देश दिया। हरियाणा राज्य, हुडा और प्रतिवादी- आरएन पराशर को नोटिस जारी करते हुए जनहित याचिका। इस तरह यह मामला अंततः इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

5. अनुचित लाभ के लाभार्थी आरएन पराशर सहित प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी किए जाने के बाद, उन्होंने अपने जवाब दाखिल किए हैं और अपने संबंधित दावों के समर्थन में मौखिक तर्क भी दिए हैं।

6. एमिक्स क्यूरी के रूप में उपस्थित अधिवक्ता श्री अरुण नेहरा ने प्रस्तुत किया कि यह मामला राज्य और उसके पदाधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। वर्तमान मामले में, आरएन पराशर, एक वरिष्ठ नौकरशाह, जो शुरू में अपनी भूमि को अधिग्रहण से बचाने में सक्षम थे, हालांकि पहले दो बार अधिसूचित किया गया था, हालांकि, जब अंततः एक छोटा सा हिस्सा अधिग्रहित किया गया था, तो उसे भी अधिक समय के बाद उनके द्वारा जारी किया गया था। कलेक्टर द्वारा पुरस्कार पारित होने और राज्य द्वारा भूमि का कब्जा लेने के 6 वर्ष। किसी भी भूमि पर कब्जा हो जाने के बाद उसे अधिग्रहण से मुक्त करने की कोई शक्ति राज्य के पास निहित नहीं है। वास्तव में, जमीन जारी करने की आड़ में, आरएन पराशर को 2009 के विकसित सीडब्ल्यूपी नंबर 2098 [4] सेक्टर 4, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला में दो कनाल का प्लॉट आवंटित किया गया था, जिसकी कीमत स्वर्गीय शर्त पर करोड़ों रुपये थी। उसकी अधिग्रहीत भूमि से संबंधित प्राप्त मुआवजे की राशि ब्याज सहित और विकास शुल्क के रूप में एक छोटी राशि वापस कर दी जाएगी।

7. उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ऐसी कोई नीति है, तो उसे जनता को अवगत कराया जाना चाहिए क्योंकि जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई है, वे निश्चित रूप से अपनी अर्जित भूमि के बराबर विकसित क्षेत्रों में प्लॉट लेना पसंद करेंगे। उन्हें केवल ब्याज और विकास शुल्क के साथ प्राप्त मुआवजा लौटाना है। यह तो संयोग है कि यह अवैधता इस न्यायालय के संज्ञान में आ गई, अन्यथा यह बात सरकारी फाइलों में ही दबी रह जाती। श्रीमती में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले का जिक्र करते हुए। मिरदुला जोशी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2009(1) आरसीआर (सिविल) 536 और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इसके आयुक्त बनाम वीर कुमार जैन और अन्य, 2010 (2) आरसीआर (सिविल) 851, प्रस्तुत किया गया था कि रिहाई आरएन पराशर के पक्ष में भूमि का आवंटन रद्द किये जाने योग्य है।

8. राज्य के विद्वान वकील ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने कई निर्णयों में व्याख्या की है, एक बार भूमि का कब्जा ले लिया गया था। राज्य, उसे अधिग्रहण से मुक्त नहीं किया जा सका. इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, भले ही जिस उद्देश्य के लिए इसे प्राप्त किया गया था वह अब अस्तित्व में न हो। श्रीमती

में इस न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए। मृदुला जोशी के मामले (सुप्रा) में यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त मामले में, कुछ भूमि मालिकों के पक्ष में भूमि की रिहाई को इस अदालत द्वारा समान परिस्थितियों में रद्द कर दिया गया था। हालाँकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तथापि, केवल निर्णय के पैराग्राफ 22 (डी) में निहित निर्देशों के संबंध में अंतरिम रोक है, जो अधिग्रहण से संबंधित कुछ मामलों पर व्यापक निर्देश जारी करने का प्रावधान करता है। ज़मीन का। वह यह प्रस्तुत करने में काफी निष्पक्ष थे कि जैसा कि निदेशक, शहरी संपदा के 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 के नोट में देखा गया है [5] 13.5.2006, भूमि का कब्ज़ा वास्तव में राज्य द्वारा ले लिया गया था।

9. भले ही प्राधिकारी, जिसके आदेश के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही में कब्ज़ा लेने के काफी समय बाद भूमि को मुक्त करने का निर्देश दिया गया था, कानून की तय स्थिति को देखते हुए रिहाई के आदेश का बचाव करने में सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी विद्वान वकील उपस्थित हुए हुडा ने प्रतिवादी- आरएन पराशर को प्लॉट नंबर 190 सेक्टर 4, एमडीसी, पंचकुला आवंटित करने में हुडा की कार्रवाई को उचित ठहराने की मांग करते हुए दावा किया कि यह हुडा द्वारा केवल भूमि का आदान-प्रदान था, जो कि धारा 15 के संदर्भ में स्वीकार्य है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (संक्षेप में, ' हुडा अधिनियम ')। उन्होंने इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया कि प्रतिवादी- आरएन पराशर के स्वामित्व वाली भूमि का आकार शुरू में त्रिकोणीय था। पहले भी जब जमीन का कुछ हिस्सा अधिग्रहण से छूट गया था, तो उसे विकास योजना का हिस्सा बना दिया गया था और हुडा द्वारा उसे शुरू में उसके स्वामित्व वाली जमीन के बदले उचित आकार का प्लॉट दिया गया था। उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि प्रासंगिक समय पर उनके साथ किसी एक्सचेंज डीड पर हस्ताक्षर किए गए थे या नहीं।

10. प्रतिवादी-आरएन पराशर की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपने मुवक्किल को उसके द्वारा की गई या किसी अन्य प्राधिकारी से की गई अवैधता में बचाने के प्रयास में प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है, जिसके लिए इस अदालत ने न्यायिक नोटिस लिया। यह महज एक व्यक्ति से संबंधित भूमि है, जिसे राज्य ने उसके दावे को उचित और प्रामाणिक पाते हुए अधिग्रहण से मुक्त कर दिया है। इससे कोई भी तीसरा पक्ष प्रभावित नहीं होता है और इस अदालत को सरकार की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह उस तरह का मामला नहीं था जिसमें इस अदालत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि भूमि प्रतिवादी- आरएन पराशर के पक्ष में वर्ष 2006 में ही जारी कर दी गई थी। अब उस कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि गंगा नदी के पुल के नीचे बहुत पानी बह चुका है और पार्टियों ने अपना स्थान बदल लिया। उन्होंने आगे कहा कि हुडा अधिनियम के तहत भूमि जारी करने पर कोई रोक

नहीं है। अदालत के पूछने पर, विद्वान वकील ने सीडब्ल्यूपी संख्या 2098/2009 [6] में स्पष्ट रूप से कहा कि अधिनियम या हुडा अधिनियम के तहत कोई सक्षम प्रावधान नहीं है। वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सकते थे कि भूमि राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई थी और हुडा केवल इसका लाभार्थी था, इसलिए, हुडा द्वारा भूमि जारी करने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने हुडा के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क का भी समर्थन किया, जिसमें दावा किया गया था कि यह हुडा द्वारा भूमि के बदले भूमि का आदान-प्रदान था, जिसे अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया था और इसमें कुछ भी अवैध नहीं था। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि श्रीमती में इस न्यायालय के फैसले के बाद से। मिरदुला जोशी का मामला (सुप्रा) पहले से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, यह न्यायालय उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर सकता है।

11. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

12. पक्षों की संबंधित दलीलों पर विचार करने से पहले मामले के तथ्यों पर संक्षेप में गौर करना उचित होगा।

13. प्रतिवादी-आरण पराशर ने वर्ष 1980 में मनसा देवी मंदिर के पास भैंसा टिब्बा गांव में 7 कनाल और 5 मरला जमीन खरीदी। उनका दावा है कि उपरोक्त जमीन राज्य से ऋण लेने के बाद खरीदी गई थी। पहली बार, उपरोक्त भूमि को अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 27.8.1981 द्वारा अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया गया था। प्रतिवादी-आरण पराशर द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए भूमि को अधिग्रहण से बाहर कर दिया गया। दिनांक 23.4.1985 की अधिसूचना द्वारा भूमि को फिर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया गया था। प्रतिवादी-आरण पराशर ने फिर से अधिग्रहण पर आपत्ति जताई। उनके द्वारा दाखिल की गई आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उसे एट की धारा 6 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया। प्रतिवादी-आरण पराशर द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रासंगिक समय पर, वह मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा के रूप में तैनात थे। हालाँकि, उन्होंने दावा किया कि इस मामले से संबंधित फ़ाइल का निपटान उनके द्वारा नहीं किया गया था और भूमि अधिग्रहण नहीं करने का निर्णय तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री की सहमति से विभाग के सचिव द्वारा लिया गया था।

14. 5.5.1987 को एक और अधिसूचना जारी की गई जिसमें सड़क निर्माण के उद्देश्य से 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2098 [7] भूमि का हिस्सा हासिल करने का प्रस्ताव था। इस प्रक्रिया

में, प्रतिवादी- आरएन पराशर के पास 5 कनाल और 14 मरला भूमि शेष छोड़कर एक कनाल और 11 मरला भूमि का अधिग्रहण किया गया।

15. 11.9.1997 को जारी बाद की अधिसूचना के अनुसार, शेष 5 कनाल और 14 मरला भूमि (2883 वर्ग मीटर) का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया था। प्रतिवादी- आरएन पराशर ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपतियां दायर कीं। प्रतिवादी- आरएन पराशर को सुनने का अवसर देने और साइट का निरीक्षण करने के बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (संक्षेप में, 'कलेक्टर') ने बताया कि मौके पर, 25x14 फीट और 280 पर 'ए' श्रेणी के निर्माण का एक कमरा था। वर्ग गज, खम्भे पर लालटेन थी। उन्होंने 330 वर्ग गज भूमि अवमुक्त करने की अनुशंसा की। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करते समय, 0.13 एकड़ (535 वर्ग मीटर) भूमि, जिस पर निर्माण मौजूद था, को छोड़ दिया गया था, जबकि 0.58 एकड़ (2348 वर्ग मीटर) भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई थी। हालाँकि, फिर भी प्रतिवादी-आरएन पराशर संतुष्ट नहीं थे और प्रभुत्वशाली स्थिति में होने के कारण पुरस्कार की घोषणा में देरी करने में सक्षम थे और अंतराल के दौरान अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करके 0.37 एकड़ (1500 वर्ग मीटर) भूमि को मुक्त कराया। मंत्री की समिति और अंततः यह केवल 0.21 एकड़ (848 वर्ग मीटर) भूमि थी, जिसके लिए कलेक्टर द्वारा 5.9.2000 को पुरस्कार की घोषणा की गई थी।

16. जैसा कि एजेंडा आइटम नंबर ए-98वें (1)-सप्ल में देखा गया है। हुडा के अनुसार, मूल रूप से प्रतिवादी आरएन पराशर के स्वामित्व वाले भूखंड का आकार त्रिकोणीय था। भूमि का 2,035 वर्ग मीटर का हिस्सा, जो कलेक्टर द्वारा पुरस्कार की घोषणा के चरण तक जारी किया गया था, उसे भी विकास शुल्क के रूप में केवल ₹ 5,85,870/- जमा करने पर नियमित आकार के भूखंडों में दे दिया गया था।

17. अवार्ड की घोषणा के बाद भूमि पर शासन का कब्ज़ा हो गया। प्रतिवादी- आरएन पराशर ने असंतुष्ट होकर, कलेक्टर के समक्ष आपतियां दायर कीं, जिन्हें विद्वान जिला न्यायाधीश, पंचकुला को भेजा गया, जिन्होंने अपने फैसले दिनांक 21.10.2002 के तहत 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 के फैसले को खारिज कर दिया। [8] कलेक्टर को उचित होना चाहिए।

18. प्रतिवादी- आरएन पराशर ने निचली अदालत के फैसले से व्यथित होकर इस अदालत के समक्ष 2003 का आरएफए नंबर 818 दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पुरस्कार की घोषणा और कलेक्टर द्वारा भूमि का कब्ज़ा लेने के 8 साल से अधिक समय बाद और मुआवजे में वृद्धि की मांग करते हुए इस अदालत के समक्ष अपील दायर करने के 5 साल बाद, प्रतिवादी- आरएन पराशर द्वारा इस अदालत के समक्ष सीएम नंबर के साथ आवेदन दायर

किया गया था। 2008 के 8834-सीआई में अपील वापस लेने की अनुमति मांगी गई। प्रतिवादी-आरण पराशर की प्रार्थना को प्रामाणिक मानते हुए अपील को 11.9.2008 को वापस लेते हुए खारिज करने की अनुमति दी गई।

19. प्रतिवादी- आरण पराशर के लिए दुर्भाग्य यह था कि बाद में कुछ अन्य भूमि मालिकों ने उनके द्वारा दायर अपील को वापस लेने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर किए, जिसमें मुआवजे में वृद्धि के लिए भी प्रार्थना की गई थी। मुआवजे में वृद्धि की मांग को लेकर दायर की गई अपीलों को वापस लेने के लिए भूमि मालिकों द्वारा की गई प्रार्थना काफी अभूतपूर्व थी क्योंकि अंततः उनकी अपीलें खारिज की जा सकती थीं। उस बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध भी, उनके पास अपने अन्य उपाय थे। इन परिस्थितियों में, इस अदालत ने राज्य के वकील से स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि भूमि मालिकों द्वारा दायर अपीलें क्यों वापस ली जा रही हैं। उनसे यह भी बताने को कहा गया कि किन परिस्थितियों में प्रतिवादी आरण पराशर ने पहले अपनी अपील वापस ले ली थी।

20. इसके जवाब में, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, फरीदाबाद का हलफनामा दायर किया गया था जिसमें 1999 के आरण संख्या 2540 से 2543 में भूमि मालिकों द्वारा अपील वापस लेने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई थी। उपरोक्त अपीलों में भूमि मालिकों ने अपनी अपीलें वापस ले लीं, संक्षेप में यह उल्लेख किया गया है कि उन मामलों में संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि इस न्यायालय द्वारा कम कर दी गई थी। यह पाते हुए कि राज्य मुआवजे में कमी की मांग करने वाले उन भूमि मालिकों के मामलों में अपील में नहीं था, भले ही 2009 के सभी सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [9] अन्य मामलों में अपील दायर की गई थी, भूमि मालिकों ने उन अपीलों को वापस लेने की अनुमति मांगी ताकि उनके मामलों में इस अदालत द्वारा अंततः निर्धारित की गई दर से अधिक दर पर मुआवजा देने के निचली अदालत के फैसले को रद्द नहीं किया गया है। हालाँकि, बाद में, उपरोक्त मामलों में राज्य द्वारा दायर की गई अपीलों के साथ-साथ उन्हें दोबारा दाखिल करने में 8 साल और 251 दिनों की देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन भी इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आए। पुनः दाखिल करने में देरी की माफी मांगने के कारणों को पर्याप्त नहीं पाते हुए, उन आवेदनों के साथ-साथ अपीलों को भी इस अदालत ने दिनांक 7.9.2010 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था।

21. हालाँकि, जहाँ तक प्रतिवादी- आरण पराशर से संबंधित अपील का संबंध है, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकुला ने दिनांक 27.11.2018 को हलफनामा दायर किया। 2008 में बताया गया कि उनकी जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई है।

22. यह इस स्तर पर है कि राज्य की मनमानी कार्रवाई सामने आई, जिसके तहत प्रतिवादी-आरएन पराशर की भूमि, जिसके लिए पुरस्कार 5.9.2000 को घोषित किया गया था और राज्य द्वारा कब्जा ले लिया गया था, को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया था। 24.7.2006 को माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत और उसके परिणामस्वरूप, जारी की गई भूमि का कब्जा सौंपने के बजाय, प्लॉट नंबर 190, सेक्टर 4, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला, 846 वर्ग मीटर माप प्रतिवादी को आवंटित किया गया था- आरएन पराशर ने कथित तौर पर हुडा द्वारा जारी की गई जमीन के बदले में... उपरोक्त कार्रवाई को स्पष्ट रूप से सत्ता के जबरदस्त दुरुपयोग का हिस्सा पाते हुए, इस अदालत ने इस मुद्दे को एक जनहित याचिका के रूप में मानना उचित समझा।

23. तथ्यों के अनुक्रम से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, संक्षेप में, जो सामने आया है वह यह है कि यह एक ऐसा मामला है जहां सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी सफलतापूर्वक बचत करके अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने में सक्षम था। 1981 से अधिग्रहण के बाद से उनके स्वामित्व वाली भूमि। अधिनियम के प्रावधानों को उनकी विलासितापूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए दबा दिया गया था, जो अपने महलनुमा घर के निर्माण के लिए 0.5 एकड़ (2,035 वर्ग मीटर) से संतुष्ट नहीं थे। 2009 के हुडा सीडब्ल्यूपी नंबर 2098 [10] द्वारा उन्हें एक प्रमुख स्थान पर 846 वर्ग मीटर का एक प्लॉट उपहार में देने की मांग की गई थी, केवल इस शर्त पर कि वह उन्हें प्राप्त मुआवजे की राशि ब्याज और कुछ छोटे विकास शुल्क के साथ वापस कर देंगे। . प्रासंगिक समय में भूखंड का बाजार मूल्य करोड़ों रुपये में चल रहा था। राज्य या हुडा के विद्वान वकील द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि भूमि की रिहाई के लिए प्रतिवादी-आरएन पराशर के मामले पर राज्य की किसी नीति के तहत विचार किया गया था, जिसे बड़े पैमाने पर जनता को अवगत कराया गया था या यह केवल था किसी व्यक्ति पर किया गया उपकार। यदि कोई नीति बनाई जाती है, तो बड़े पैमाने पर जनता उसका लाभ लेने की हकदार है। केवल सत्ता के गलियारे तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

24. इससे पहले कि हम पक्षों के विद्वान वकील की संबंधित दलीलों पर विचार करें, अधिनियम की धारा 16 और 48 और हुडा अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों को निकालना उचित होगा , जो निम्नानुसार हैं:

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 16 और 48 "16. कब्जा लेने की शक्ति - जब कलेक्टर ने धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया है, तो वह भूमि का कब्जा ले सकता है, जो तब पूरी तरह से सरकार में निहित होगी, से मुक्त सभी बाधाएँ.

48. अधिग्रहण पूरा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पूरा न होने पर मुआवजा दिया जाएगा।-

(1) धारा 36 में दिए गए मामले को छोड़कर, सरकार किसी भी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसका कब्जा नहीं है। लिया गया।

(2) जब भी सरकार ऐसे किसी अधिग्रहण से पीछे हटती है, तो कलेक्टर नोटिस या उसके तहत किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप मालिक को हुए नुकसान के लिए देय मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा, और इच्छुक व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करेगा। 2009 की उक्त सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [11] भूमि से संबंधित इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अभियोजन में उनके द्वारा उचित रूप से खर्च की गई सभी लागतों के साथ।

(3) इस अधिनियम के भाग III के प्रावधान, इस धारा के तहत देय मुआवजे के निर्धारण के लिए, जहां तक संभव हो, लागू होंगे"।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 15 ,

15. भूमि का निपटान.- (1) इस अधिनियम और उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन, प्राधिकरण निम्नलिखित का निपटान कर सकता है -

(ए) राज्य सरकार द्वारा उसके द्वारा अर्जित की गई या उसे हस्तांतरित की गई कोई भी भूमि, उस पर कोई विकास कार्य किए बिना या किए बिना; या

(बी) ऐसी कोई भी भूमि, ऐसा विकास करने या करने के बाद, जैसा वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जैसा वह विकास सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे।

(2) इस अधिनियम में किसी भी चीज़ को उपहार के माध्यम से भूमि के निपटान के लिए प्राधिकारी को सक्षम करने के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन इस शर्त के अधीन, इस अधिनियम में भूमि के निपटान के संदर्भ को किसी भी तरीके से उसके निपटान के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।, चाहे बिक्री, विनिमय या पट्टे के माध्यम से या किसी सुखभोग अधिकार या विशेषाधिकार के सृजन द्वारा या अन्यथा।

(3) यहां पहले से निहित प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण अपनी किसी भी भूमि या भवन को ऐसे नियमों और शर्तों पर बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है, चाहे वह नीलामी, आवंटन या अन्यथा हो।

(4) 2009 की उप-धारा (1) सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [12] के तहत किसी भी हस्तांतरण के लिए प्रतिफल राशि का भुगतान प्राधिकरण को ऐसे तरीके से किया जाएगा जो नियमों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(5) तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी भूमि या भवन या दोनों, जैसा भी मामला हो, तब तक प्राधिकरण का बना रहेगा जब तक कि संपूर्ण प्रतिफल राशि ब्याज और अन्य राशि के साथ न मिल जाए। यदि कोई हो, तो प्राधिकरण को ऐसी भूमि या भवन या दोनों की बिक्री के कारण भुगतान किया जाता है।

(6) जब तक विनियमों में प्रदान की गई शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक अंतरिती प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के अलावा भूमि या भवन में अपने अधिकारों को हस्तांतरित नहीं करेगा, जो ऐसे नियमों और शर्तों पर दी जा सकती है, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझ सकता है।।"

25. अधिनियम की धारा 16 के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार की घोषणा के बाद , कलेक्टर उस भूमि पर कब्जा करने के लिए स्वतंत्र है, जो उसके बाद सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाएगी। वर्तमान मामले में, यह रिकॉर्ड पर स्वीकृत स्थिति है जैसा कि निदेशक, शहरी संपदा के दिनांक 13.5.2006 के नोट से स्पष्ट है कि भूमि का कब्जा शुरू में ले लिया गया था। इसके साथ ही यदि अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों पर विचार किया जाए, तो यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि राज्य को केवल उस भूमि को अधिग्रहण से हटाने की स्वतंत्रता दी गई है, जिस पर कब्जा नहीं लिया गया है। भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के संदर्भ में अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कई बार विचार के लिए आये।

26. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम विष्णु प्रसाद शर्मा और अन्य , एआईआर 1966 एससी 1593 में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि एक बार सरकार ने भूमि पर कब्जा कर लिया, तो वह अधिग्रहण से पीछे नहीं हट सकती। उसका प्रासंगिक अनुच्छेद 19 नीचे दिया गया है:

2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [13] "19.... इस शक्ति का प्रयोग कलेक्टर द्वारा धारा 11 के तहत पुरस्कार देने के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन एस के तहत कब्जा लेने से पहले भी किया जा सकता है।

15. धारा 48(2) ऐसे मामले में मुआवजे का प्रावधान करती है। इसलिए, यह तर्क कि धारा 48(1) ही एकमात्र तरीका है जिससे सरकार अधिग्रहण से पीछे हट सकती है, कोई बल नहीं है क्योंकि सरकार हमेशा धारा के तहत अधिसूचनाओं को रद्द कर सकती है। 4 और 6 सामान्य धारा अधिनियम की धारा 21 के तहत अपनी शक्ति के आधार पर और इस शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा कलेक्टर को धारा 7 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश देने से पहले किया जा सकता है। धारा 48(1) उन मामलों के लिए एक विशेष प्रावधान है जहां अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 9(1) के तहत नोटिस जारी करने के चरण से आगे बढ़ गई है और यह धारा 48(2) के तहत मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करती है। 48(3) . इसलिए, हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि धारा 48 (1) के तहत आदेश के बिना धारा 4 के तहत अधिसूचना बकाया रहनी चाहिए। इसे जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 21 के तहत सरकार द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और धारा 48(1) से पता चलता है कि एक बार सरकार ने कब्जा कर लिया तो वह अधिग्रहण से पीछे नहीं हट सकती। इससे पहले वह एसएस के तहत अधिसूचना रद्द कर सकती है। 4 और 6 या यह धारा 48(1) के तहत अधिग्रहण से हट सकता है ..."

(जोर दिया गया)।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों पर बाद में हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल और अन्य बनाम श्री अविनाश शर्मा, एआईआर 1970 एससी 1576 में विचार किया गया। उसका प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिया गया है:

"लेकिन वहां की टिप्पणियां अपीलकर्ता के मामले में सहायता नहीं करती हैं। टिप्पणियों में यह स्पष्ट रूप से निहित है कि धारा 17(1) के तहत एक अधिसूचना के अनुसार कब्जा लेने के बाद भूमि सरकार में निहित है और अधिसूचना रद्द नहीं की जा सकती है सामान्य धारा अधिनियम 2009 की धारा 21 सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [14] के तहत , न ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना को वापस लिया जा सकता है। कोई अन्य दृष्टिकोण राज्य सरकार को टालने में सक्षम करेगा एक सामान्य शक्ति पर भरोसा करके विशिष्ट प्रावधान। जब धारा 17(1) के तहत भूमि का कब्जा लिया जाता है, तो भूमि सरकार में निहित हो जाती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा सरकार में वैधानिक रूप से निहित भूमि मूल मालिक को वापस कर दी जाए अधिसूचना को रद्द करना मात्र है।" (महत्व जोड़ें)

28. इसके बाद, बेंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम आर. हनुमैया और अन्य , (2005) 12 एससीसी 508 में, प्रताप बनाम राजस्थान राज्य में पहले के निर्णयों का जिक्र करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आधिपत्य , (1996) 3 एससीसी 1; मोहन सिंह

बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण , (1997) 9 एससीसी 132 और प्रिंटर्स (मैसूर) लिमिटेड बनाम एमए रशीद , (2004) 4 एससीसी 460 ने कानून के पहले के प्रतिपादन को दोहराया जिसमें कहा गया था कि राज्य ने कब्जा कर लिया है। अधिग्रहीत भूमि, इसे अधिग्रहण से वापस नहीं लिया जा सकता था। उसके प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे निकाले गए हैं:

"45. फिर से प्रताप बनाम राजस्थान राज्य , (1996) 3 एससीसी 1) में, यह दोहराया गया था कि एक बार कब्जा ले लिया गया और भूमि सरकार में निहित हो गई तो सरकार भूमि अधिग्रहण की धारा 48 के तहत अधिग्रहण से पीछे नहीं हट सकती अधिनियम। इस न्यायालय द्वारा मोहन सिंह बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण , (1997) 9 एससीसी 132 और प्रिंटर्स (मैसूर) लिमिटेड बनाम एमए रशीद , (2004) 4 एससीसी 460 में भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया था।

46. प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा वर्ष 1966 में भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित होने के बाद लिया गया था। इसके बाद, भूमि सरकार में निहित हो गई जिसे बाद में अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती सीआईटीबी को हस्तांतरित कर दिया गया। भूमि के स्वामित्व और उस पर कब्जा लेने के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अधिग्रहण के लिए 2009 की अधिसूचना सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [15] को वापस नहीं लिया जा सकता था या रद्द नहीं किया जा सकता था। भूमि को वैधानिक रूप से राज्य सरकार में निहित करने के बाद सामान्य धारा अधिनियम की धारा 21 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।"

29. मंदिर श्री सीतारामजी उर्फ श्री सीताराम भंडार बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य , एआईआर 2005 एससी 3581 में भी यही स्थिति थी ; नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम महेश दत्ता और अन्य , 2010(2) आरसीआर (सिविल) 109 और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण इसके आयुक्त बनाम वीर कुमार जैन और अन्य , 2010(2) आरसीआर (सिविल) 851।

30. यह मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष भी कई मामलों में विचार के लिए आया, जहां ऐसी समान परिस्थितियों में राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग को रद्द कर दिया गया था। गुरकिरपाल सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त (राजस्व) और सचिव, पंजाब सरकार, राजस्व विभाग और अन्य , (2008-3) पीएलआर 740; का संदर्भ लिया जा सकता है ;

31. हरि चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य , 2009(4) आरसीआर (सिविल) 467 में , इस न्यायालय ने बिल्डरों के पक्ष में मनमाने ढंग से भूमि जारी करने में राज्य के साथ-साथ हुडा के आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी की। उसका प्रासंगिक अनुच्छेद 13 नीचे दिया गया है:

"13. याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 धारा 3(i) की पहली आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने और उनके पास लाइसेंस होने के बाद उन्हें पूर्ण मालिक नहीं माना जा सकता है। एहसान तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि कानून में वे यह तर्क देने में सक्षम न हों कि संबंधित भूमि पर उनका स्वामित्व है। इस संदर्भ में, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का एक हिस्सा जारी करने की सरकार की नीति पर विचार किया जाना चाहिए। एक बार, शहरी क्षेत्र में एक सेक्टर के विकास के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है , आसपास के सीडब्ल्यूपी नंबर 2098 2009 [16] क्षेत्र में भूमि की दरें और उस भूमि के संबंध में जो नहीं है आम तौर पर अधिग्रहण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी भूमि के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक विकसित होने की संभावना है। एक बार उस क्षेत्र के संबंध में स्थिति जो धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचित नहीं की गई है , तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद अधिग्रहण से मुक्त किया जाने वाला क्षेत्र अत्यधिक कीमती हो जाएगा। कॉलोनाइजरों को बड़ी मात्रा में भूमि जारी करने में, राज्य या उसकी एजेंसियां उस सार्वजनिक उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ा रही हैं जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, बल्कि किसी कॉलोनाइजर या निजी व्यक्ति के पक्ष में भूमि जारी करके समाज को नुकसान होगा। अपने निजी हित को आगे बढ़ाने के लिए. हमारा दृढ़ मत है कि ऐसा पाठ्यक्रम प्रतिवादी-राज्य के लिए उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का विवेकाधिकार उन व्यक्तियों के पक्ष में उपलब्ध है, जिन्होंने धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले घर, कारखाने आदि बनाए थे , लेकिन उन लोगों को लाइसेंस देने में किसी विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने किसी में प्रवेश कर लिया है। धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि मालिक के साथ सहयोग समझौता. यह सत्ता का रंगीन प्रयोग होगा क्योंकि जिस भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करने की मांग की गई है उसे निजी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया जाएगा जो कि प्रतिष्ठित डोमेन के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए, हम ऐसे कॉलोनाइजर के पक्ष में लाइसेंस देने की राज्य सरकार की नीति को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसकी धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले भूमि में कोई रुचि नहीं थी और जिसने सहयोग समझौते में प्रवेश करके या स्वामित्व अधिकार प्राप्त करके ब्याज अर्जित किया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के बाद । धारा 4 के तहत 2009 की अधिसूचना सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [17] जारी होने के बाद प्रतिवादी-राज्य भूमि मालिकों या एक निजी कॉलोनाइजर को लाइसेंस जारी करने का हकदार नहीं होगा। "

32. दिल्ली असम रोडवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य, 2008(3) आरसीआर (सिविल) 389 में, वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन से संबंधित एक मामले के संदर्भ में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच की शुरुआती टिप्पणियां सेक्टर 44,

गुडगांव वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर पूरी तरह लागू होते हैं। वही नीचे निकाला गया है:

"यदि कानून के स्थापित सिद्धांतों का खुलेआम उन लोगों द्वारा उल्लंघन किया जाता है, जिन्हें उन सिद्धांतों को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है, तो भोली-भाली जनता इस धारणा के साथ चलने के लिए बाध्य है कि प्रणाली केवल बाहरी विचारों पर चलती है, न कि प्रासंगिक विचारों पर। जब कानून के तहत घोषित किया जाता है संविधान का अनुच्छेद 141 प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी हो जाता है, तब कम से कम यह मान लेना सुरक्षित है कि पार्टियों को इसकी जानकारी है। जब लालच से भरे लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि कानून के स्थापित सिद्धांतों को स्थगित किया जा सकता है, तब ऐसे लोग ऐसे सिद्धांतों को हराने की हिम्मत और आत्मविश्वास हासिल कर लेते हैं। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिकाओं का यह सेट ऐसे व्यक्तियों की सोच को उजागर करता है, जिन्हें शायद उम्मीद थी कि उनके कृत्यों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और वे अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। बिना पकड़े गए। लेकिन सतर्क याचिकाकर्ता आगे आकर तयशुदा कानून को ठंडे बस्ते में डालने के अपने मंसूबों और नापाक इरादों को उजागर कर रहे हैं।"

33. अधिनियम की धारा 48 के तहत शक्ति के प्रयोग के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए , कुछ तथ्यों को बताना उचित होगा कि पुरस्कार की घोषणा और अधिग्रहण के लगभग 6 साल बाद भूमि को मुक्त करने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। राज्य द्वारा कब्जे की पहल प्रतिवादी- आरण पराशर द्वारा की गई थी। पत्र दिनांक 13.5.2005 को उनके द्वारा सरकार के वित्तीय आयुक्त और प्रमुख सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को संबोधित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी भूमि का अधिग्रहण 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2098 [18] पर राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किया गया था। अन्यथा, अधिग्रहण का कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि दो कनाल का प्लॉट नंबर 190, सेक्टर 4, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स अधिग्रहीत भूमि से बनाया गया था और वह अभी भी बिना आवंटित पड़ा हुआ है। इसके बाद दिनांक 14.9.2005 को संचार किया गया। सुब्रमण्यम असारी बनाम राज्य सचिव, 17 एमएलजे 557 के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले का संदर्भ यह प्रस्तुत करने के लिए किया गया था कि ऐसे मामलों में भी जहां मालिक द्वारा मुआवजा प्राप्त किया गया था, उसे वापस किया जा सकता है और जमीन मालिक को वापस दी जा सकती है। .

34. प्रदेश के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य के बयान से पता चलता है कि वह किस प्रकार एक पुराने फैसले का हवाला देकर सरकार को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले इसके विपरीत विचार रख रहे थे तत्संबंधी. उन्होंने उन उदाहरणों का भी हवाला दिया जहां पहले सरकार द्वारा किसी अन्य पसंदीदा व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग किया गया था। इस

पत्र की प्रति माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा को भी भेजी गई। प्रतिवादी-आरएन पराशर के अनुरोध पर, निदेशक, शहरी संपदा द्वारा 13.5.2006 को निम्नलिखित शर्तों में एक नोट डाला गया था:

"साइट का निरीक्षण 5.5.2006 और फिर 9.5.2006 को किया गया था। भूमि का स्थान कृपया प्लैग 'X' पर योजना पर देखा जा सकता है। जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया था उसका मूल आकार लाल रंग में दिखाया गया है और नियमित भूखंड के रूप में जारी की गई भूमि को ए, बी, सी और डी के रूप में चिह्नित किया गया है और इसकी माप 2035 वर्ग मीटर है। निकटवर्ती भूखंड संख्या 187 से 190 तक अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं। जो निर्माण किया गया है श्री आरएन पराशर द्वारा किए गए कार्य को साइट प्लान पर 'वाई' ध्वज पर दिखाया गया है। हुडा द्वारा आवंटित 2 कनाल श्रेणी के भूखंडों के मामले में भवन उपनियमों के अनुसार अनुमेय सेट बैक सहायक क्षेत्र की ओर तीन मीटर और दूसरी तरफ 2.5 मीटर है। श्री पराशर द्वारा किए गए निर्माण से पता चलता है कि एक तरफ का सेट बैक लगभग एक मीटर है। 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2098 [19] को उचित सेट बैक प्रदान करने के लिए और प्लॉट नंबर 187 से 190 तक को बनाए रखने के लिए भी। इन भूखंडों की चौड़ाई 18 मीटर से घटाकर 17 मीटर करने और श्री को 4 x 47 मीटर की भूमि की एक पट्टी प्रदान करने का प्रस्ताव है। आरएन पराशर. यह आवंटन की सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए प्राधिकरण की मंजूरी की आवश्यकता होगी और इसे मौजूदा दरों पर आवंटित करने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा श्री को प्राप्त हुआ था। आरएन पराशर ने ध्वज 'ए' पर अपने पत्र में उल्लेख किया है कि अधिग्रहीत भूमि सरकार द्वारा मालिक को वापस की जा सकती है। यहां तक कि जहां मालिक को मुआवजा मिल चुका है। उन्होंने गांव देवीनगर में खसरा नंबर 389/2 में आने वाली 1.02 एकड़ जमीन जो अब सेक्टर 3, पंचकुला में पड़ती है, को वापस करने का उदाहरण भी दिया है। यह रिकॉर्ड से जांचा गया है कि सरकार ने अधिग्रहण के 10 साल बाद जमीन जारी कर दी है। आदेश की एक प्रति ध्वज 'बी' पर रखी गई है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान इस प्रकार हैं:

"अधिग्रहण पूरा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पूरा नहीं होने पर मुआवजा दिया जाएगा।

(1) धारा 36 में दिए गए मामले को छोड़कर, सरकार किसी भी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए स्वतंत्र होगी, जिस पर कब्जा नहीं लिया गया है।

(2) जब भी सरकार ऐसे किसी अधिग्रहण से पीछे हटती है, तो कलेक्टर नोटिस के परिणामस्वरूप या उसके तहत किसी भी कार्यवाही के परिणामस्वरूप मालिक को हुई क्षति के लिए देय मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा, और इच्छुक व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करेगा। उक्त भूमि से संबंधित इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अभियोजन सीडब्ल्यूपी संख्या 2098/2009 [20] में उनके द्वारा उचित रूप से खर्च की गई सभी लागतों के साथ। (3) इस अधिनियम के

भाग III के प्रावधान, इस धारा के तहत देय मुआवजे के निर्धारण के लिए, जहां तक संभव हो, लागू होंगे।"

उपरोक्त धारा 48 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सरकार। एक बार सरकार द्वारा भूमि का कब्जा ले लेने के बाद भूमि को मुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है। इस मामले में वास्तव में कब्जा ले लिया गया है.

इसे देखते हुए सरकार ऊपर 'ओ' पर दिए गए प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। "

35. इसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 24.7.2006 को निम्नलिखित नोट के साथ अनुमोदित किया गया था:

"सीएम ने श्री पराशर द्वारा दिनांक 13.5.2005 और 14.9.2005 को अपने अभ्यावेदन में बताई गई असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भूमि के शेष हिस्से को जारी करने के लिए मामले पर कार्रवाई की है, जिसके बदले में उन्हें ब्याज सहित मुआवजा राशि लौटानी होगी उस पर। सीएम ने आगे आदेश दिया है कि इस आशय का एक प्रस्ताव हुडा प्राधिकरण के समक्ष लाया जाए।"

36. इसके बाद, मामले को पूरक आइटम नंबर 1 के रूप में हुडा की 98 वीं बैठक में रखा गया था। इसका उल्लेख नोट (अनुलग्नक ए.10 श्री अरविंद शर्मा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकुला के शपथ पत्र के साथ दिनांक 27.11.2008) में किया गया था।) कि प्रतिवादी-आरएन पराशर के स्वामित्व वाली कुल भूमि 5 कनाल और 14 मरला (2,883 वर्ग मीटर) थी, जिसे 11.9.1997 को अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था। इसमें से 535 वर्ग मीटर भूमि 8.9.1998 को अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करते समय छोड़ दी गई थी। हालाँकि, पुरस्कार के समय, कुल 2,883 वर्ग मीटर भूमि में से, 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [21] की 2,035 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था और केवल 1 कनाल और 14 मरला भूमि के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी, यानी। 848 वर्ग मीटर. चेक नंबर 062808 दिनांक 5.9.2000 के माध्यम से प्रतिवादी आरएन पराशर को 4,32,354/- का मुआवजा दिया गया। हुडा ने इस अधिग्रहित जमीन के साथ-साथ आसपास की अधिग्रहित जमीन पर भी प्लॉट काट दिए थे। प्रतिवादी- आरएन पराशर के स्वामित्व वाली भूमि त्रिकोणीय आकार में थी। हालाँकि, 2,035 वर्ग मीटर का जारी क्षेत्र भी उन्हें भूखंड के नियमित आकार में दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह विशेष रूप से देखा गया कि भूमि के अधिग्रहण और उस पर कब्जा लेने के बाद, इसका उपयोग दो कनाल और एक कनाल भूखंडों की योजना बनाने के लिए किया गया था। उसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, अधिग्रहीत भूमि को कब्जे में लेने

के बाद उसे मुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 48 का उल्लंघन है। इसके अलावा, इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि किसी व्यक्ति को उसके आवेदन पर एक विशेष आवासीय भूखंड आवंटित करने की कोई प्रणाली नहीं है क्योंकि आवासीय भूखंडों का आवंटन विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके और उसके बाद झा निकालकर किया जाता है। भूखंड आवंटन के लिए सरकार के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है।

37. उपरोक्त तथ्यों को दर्ज करते हुए, एक प्रस्ताव रखा गया कि क्या 846 वर्ग मीटर के दो कनाल प्लॉट नंबर 190, सेक्टर 4, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला को प्रतिवादी- आरएन पराशर को उनके बदले में आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है। 848 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया। इस पर माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष, हुडा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही निम्नलिखित शब्दों में दर्ज की गई:

"यह निर्णय लिया गया कि श्री आरएन पराशर की 848 वर्ग मीटर भूमि का शेष हिस्सा जारी कर दिया जाए, जिसके लिए वह मुआवजे की राशि ब्याज सहित लौटा देंगे। इसके बाद इस भूमि को प्लॉट नंबर 190, सेक्टर 4 के साथ बदल दिया जाएगा। , एमडीसी, पंचकुला का क्षेत्रफल लगभग 846 वर्ग मीटर है।"

2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [22]

38. उपरोक्त कार्यवाही का अवलोकन, जो प्रतिवादी- आरएन पराशर को भूमि जारी करने के उद्देश्य से हुई थी, स्पष्ट रूप से दिखाती है कि शुरू में उन्होंने एक निर्णय का हवाला देकर संबंधित प्राधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की जो वास्तव में बाद के निर्णयों के बिल्कुल विपरीत था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की राय है कि अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा लेने के बाद, अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिग्रहण से मुक्त करने की कोई शक्ति राज्य के पास निहित नहीं है। इतना ही नहीं, भूमि को मुक्त करने का आदेश दिया गया, जबकि नोट में यह विशेष रूप से बताया गया था कि अधिनियम की धारा 48 के तहत ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है। इससे भी अधिक, प्रतिवादी- आरएन पराशर की पहले से ही जारी भूमि से सटे एक भूखंड को जारी भूमि के बदले में आवंटित किया गया था। यह विवादित नहीं है कि भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1997 में किया गया था और 2006 तक, जब इसका एक हिस्सा प्रतिवादी- आरएन पराशर को जारी करने का निर्देश दिया गया था, हुडा ने भूमि का उपयोग एक कनाल और दो कनाल के भूखंडों को तराशने के लिए किया था और उन्हें भी बिक्री के लिए पेश किया गया होगा। यह विशेष भूखंड, जो प्रतिवादी- आरएन पराशर की पहले से ही जारी भूमि से सटा हुआ था, को कभी भी बिक्री के लिए क्यों नहीं रखा गया, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भले ही उसकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, लेकिन फिर भी वह हुडा के साथ बिक्री न करने का प्रबंधन करने में सक्षम था। बगल का प्लॉट बिक्री के लिए ताकि किसी भी सुविधाजनक समय पर वह अपनी अर्जित भूमि के बदले में वह प्लॉट आवंटित करा सके।

39. यदि कानून के प्रतिपादन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में माना जाता है, तो इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही के अनुसरण में राज्य द्वारा एक बार भूमि का कब्जा ले लिया गया है, इसके तहत शक्ति भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 48 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर स्वीकृत स्थिति यह है कि भूमि का कब्जा ले लिया गया था। तदनुसार, अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा लेने के छह साल बाद उसे मुक्त करने में राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग और कुछ नहीं बल्कि शक्ति का खुला दुरुपयोग है।

2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2098 [23]

40. राज्य का रुख जिसके तहत वह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पारित किए जाने के बावजूद भूमि जारी करने के आदेश का बचाव करने में सक्षम नहीं था, यह सवाल उठाता है कि ऐसे आदेश क्यों पारित किए जाते हैं, जो बचाव योग्य नहीं हैं। इस पर अधिकारियों को विचार करना होगा।

41. हुडा और प्रतिवादी- आरएन पराशर के विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए तर्कों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे केवल हताशा की प्रकृति में हैं। हुडा द्वारा प्रतिवादी आरएन पराशर के पक्ष में 846 वर्ग मीटर के भूखंड के आवंटन को विनिमय के रूप में उचित ठहराने की मांग की गई है। एक बार जब राज्य द्वारा प्रतिवादी-आरएन पराशर के पक्ष में भूमि की रिहाई को अवैध और मनमाना माना जाता है, तो विनिमय का कोई सवाल ही नहीं है और परिणामस्वरूप भूखंड का आवंटन भी हो जाता है। एक अन्य कारक, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि श्री आरपी गुप्ता, प्रशासक, हुडा (मुख्यालय), पंचकुला के दिनांक 17.7.2009 के हलफनामे में, यह रुख अपनाया जाना चाहिए कि हुडा अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में, 1977, इसने केवल राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया था, जबकि बहस के समय, लिया गया रुख अलग था।

42. प्रतिवादी- आरएन पराशर के विद्वान वकील द्वारा यह दावा करने के लिए उठाया गया तर्क कि इसमें कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं था, भी पूरी तरह से गलत कल्पना है। एक बार यह पाया गया कि प्रतिवादी- आरएन पराशर के पक्ष में भूमि की रिहाई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसका राज्य भी बचाव नहीं कर सकता था, संपत्ति राज्य में निहित थी। राज्य जनता का ट्रस्टी है। यदि अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करके, किसी पसंदीदा व्यक्ति को कुछ लाभ दिया जाता है, तो न्यायालय हमेशा हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि यह कोई इनाम नहीं था जिसे राज्य द्वारा वितरित किया जा रहा था।

43. देरी के संबंध में तर्क भी उतना ही निराधार है। वास्तव में, यह प्रतिवादी- आरएन पराशर द्वारा भूमि जारी होने के तुरंत बाद आवेदन दाखिल न करने की एक योजनाबद्ध साजिश थी और 2006 में उन्हें एक भूखंड आवंटित किया गया था और सितंबर, 2008 में इस अदालत में आवेदन दायर किया गया था, जो हो सकता था भूमि जारी होने के तुरंत बाद 2009 का

सीडब्ल्यूपी नंबर 2098 [24] दाखिल किया। यदि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि जारी करने की पूरी प्रक्रिया में मनमानी की दलील अदालत में उठाई जाती है, तो इसका उद्देश्य देरी के कारण समानता की वकालत करना हो सकता है। भले ही किसी ने अदालत के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया हो, फिर भी यह अदालत उस व्यक्ति के प्रति पक्षपात दिखाने के लिए राज्य द्वारा किए गए स्पष्ट रूप से गैरकानूनी कृत्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती, जो संबंधित समय में राज्य में एक वरिष्ठ पदाधिकारी था।

44. ऊपर दर्ज विस्तृत कारणों के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी- आरएन पराशर के पक्ष में 848 वर्ग मीटर भूमि की रिहाई और हुडा द्वारा उनके पक्ष में प्लॉट नंबर 190, सेक्टर 4, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला का परिणामी आवंटन अलग रखे गए हैं। हुडा को निर्देश दिया गया है कि वह प्रतिवादी आरएन पराशर को उनकी जमीन की रिहाई के बदले प्लॉट नंबर 190, सेक्टर 4, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला के आवंटन के आधार पर प्राप्त राशि और उनसे वसूले गए विकास शुल्क को ब्याज सहित लौटाए। दर, जो हुडा द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने पर आवंटियों से जमा करने की तारीख से लेकर वापसी तक वसूला जाता है।

45. हम एमिक्स क्यूरी के रूप में अदालत की सहायता करने के लिए वकील श्री अरुण नेहरा के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

(राजेश बिंदल) न्यायाधीश (एमएम कुमार) न्यायाधीश 28 अक्टूबर 2010 एमके (रिपोर्टर देखें)

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी